>

Title: Need to set up Vigilance & Monitoring Committee at the district level to monitor the programmes of Centrally Sponsored Schemes and include local MPs as the Member of Committees for the welfare of STs.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास हेतु स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ाने और उसे तीव्रता से लागू करने व पारदर्शी बनाने हेतु सरकार ने समिति बनाने का निर्णय लिया है। यह बड़ी ही खुशी की बात है किन्तु मेरे विचार से यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तर्ज पर विजिलेन्स एण्ड मानेटरिंग कमेटी जिला स्तर पर बनाया जाए तो काफी प्रभावी होगी क्योंकि वर्तमान समय में जो कमेटी बनी है उसमें विभागीय सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को ही शामिल किया गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों के शामिल न होने के कारण इन अनुसूचित जनजाति के विकास एवं कल्याण कार्यों से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को नहीं हो पाती है। परिणामस्वरूप कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ जनजाति के लोग नहीं उठा पा रहे हैं।

अतः मेरा माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरह विजिलेन्स एण्ड मानेटरिंग कमेटी प्रत्येक जिले में बनाइ जाये या राज्य स्तर की समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।